CO:MBD:2019-20: 7th June, 2019

National Stock Exchange of India Limited Listing Department Exchange Plaza, Plot No.C/1, 'G' Block Bandra-Kurla Complex Bandra (E), Mumbai-400 051	General Manager Corporate Relationship Deptt Bombay Stock Exchange Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort Mumbai 400001

Dear Sir/Madam,

Sub : Publication of Notice of AGM & Book Closure in Newspapers

Please refer to our letter no. CO:MBD:2019-20:178 dated 22nd May, 2019 informing thereby *inter alia*, that 12th Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of Central Bank of India will be held on Friday, 28th June, 2019 at 12.00 Noon on 9th Floor at the head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 and letter no. CO:MBD:2019-20 dated 6th June, 2019 informing thereby *inter alia*, that we have published Notice of abovesaid AGM and Book Closure for the purpose of AGM, in Business Standard (English) All Editions on 06.06.2019.

Further to above, we have published Notice of abovesaid AGM and Book Closure for the purpose of AGM, in Business Standard (Hindi) All Editions and in Tarun Bharat (Marathi) Mumbai Editions on 07.06.2019

A copy of clipping published in Mumbai Edition of abovesaid newspapers is enclosed herewith.

Please take the above on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For CENTRAL BANK OF INDIA

for ANAND KUMAR DAS
DEPUTY GENERAL MANAGER /
COMPANY SECRETARY

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया / CENTRAL BANK OF INDIA
मर्चेंट बैंकिंग विभाग, कें.का.
Merchant Banking Division, C.O.
मुंबई / MUMBAI

चंदर मुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 • दूरध्वनी : 2202 6428, 6638 7777 • फैक्स : (91-22) 2204 4336

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

प्रधान कार्यालय : चंदरमुखी, नरीमन पॉईंट, मुंबई - 400 021

सूचना

एतद द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की बारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार दिनांक 28 जून 2019 को दोपहर 12.00 चंदरमुखी नरीमन पॉइन्ट, मुम्बई - 400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय के 9वें माले में निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी.

1) दिनांक 31 मार्च 2019 का लेखापरीक्षित स्टैन्ड अलोन एवं समेकित तुलनपत्र, दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता, लेखों द्वारा आवृत अवधि में बैंकों के कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखों तथा तुलनपत्र पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन तथा इन्हें स्वीकार करना.

2) एफपीओ / राइट इश्यू / क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से पूंजी जुटाना.

निम्नलिखित पर विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर संशोधन या संशोधनो के बिना इसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

प्रस्ताव है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 ("योजना") एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियम, 1998 समय समय पर यथासंशोधित के अनुसार एवं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड और / अथवा इस संबंध में आवश्यक अन्य प्राधिकारी के अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों तथा स्वीकृतियों, यदि कोई हों, की शर्त पर एवं उक्त अनुमतियां प्रदान करते हुए उनके द्वारा निर्धारित शर्तों एवं संशोधनों, जिनसे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति व्यक्त की गई, की शर्त पर और सेबी (पूंजी निर्गमन एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) अधिनियम 2018 (सेबी (आईसीडीआर विनियम), सेबी (सूचीकरण बाध्यतों एवं प्रकटीकरण आवश्यकतों) विनियमन 2015 (सूचीकरण विनियमन) यथा अद्यतन संशोधित सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, यदि कोई हो, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 के अंतर्गत एवं अन्य आवश्यक प्राधिकारियों द्वारा अधिसूचनाओं/ परिपत्रों एवं स्पष्टीकरणों के तथा अन्य लागू कानूनों के अधीन एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूचीकरण करारों के अधीन, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं जिसे एतदद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे 'बोर्ड' कहा गया है) को प्रदत्त किया जाता है, जिसमें पूंजी जुटाने वाली समिति शामिल है जिसे बोर्ड ने अपनी शक्तियों (इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित) के उपयोग के लिए गठित अथवा पुनर्गठित किया जाना है, को भारत अथवा विदेश में प्रस्ताव दस्तावेज/विवरण पत्र अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से उतनी संख्या में इक्विटी शेयर्स जिनका मूल्य रु. 5000/- करोड़ (रुपए पाँच हजार करोड़ केवल) (प्रीमियम सहित, यदि हो) हो, एक या एकाधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) कंपनियों, निजी अथवा सार्वजनिक निवेश संस्थाओं, सोसायटियों, न्यासों, शोध संस्थानों, अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) यथा विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर पूंजी निवेशकों, राज्य उद्योग विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्यनिधियों, पेंशननिधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं अथवा अन्य निकायों, प्राधिकारियों अथवा निवेशकों की अन्य श्रेणियों जो विद्यमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अधीन बैंक की इक्विटी/प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं अथवा उपर्युक्त में से कोई संयोजन जिसे बैंक द्वारा उपयुक्त समझा जाय, को इस प्रकार सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित एवं आबंटित (तत्समय लागू कानून द्वारा अनुमत निर्गम के उस भाग और उस श्रेणी के व्यक्तियों को पृष्ट आबंटन और/अथवा प्रतियोगी आधार पर आरक्षण के प्रावधान सहित) करने की शक्ति प्रदान करता है कि बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी में केंद्र सरकार की धारिता किसी भी समय 51% से कम न हो.

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि अति आबंटन के विकल्प के साथ या उसके बिना अर्हताप्राप्त संस्थानों को नियोजन ऐसे निर्गम, प्रस्ताव अथवा आबंटन सार्वजनिक निर्गमन (अर्थात, अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम) और राइट्स इश्यू और/अथवा निजी तौर पर आबंटन द्वारा किया जाएगा और ऐसे प्रस्ताव, निर्गम नियोजन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 सेबी (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकतों) विनियम, 2018 ("सेबी आईसीडीआर विनियम") के प्रावधानों तथा भारिवै, सेबी और कोई अन्य प्राधिकारी जो भी लागू हो, द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों के अधीन किया जाएगा और यह उस तरीके तथा उन नियमों एवं शर्तों तथा उस समय समयांतरों में किया जाएगा जो निदेशक मंडल द्वारा अपनी पूर्ण विवेकाधीन शक्ति में उपयुक्त समझा जाता हो."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि निदेशक मंडल को सेबी आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियम तथा कोई अथवा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अपने संपूर्ण विवेक से उन निवेशकों जो बैंक के विद्यमान सदस्य हों अथवा नहीं हों, को ऐसी कीमत जो आईसीडीआर विनियमों के संगत प्रावधानों द्वारा निर्धारित कीमत से कम न हों, को इस प्रकार स्वयं तय करने और आवश्यकता पड़ने पर अग्रणी प्रबंधकों और अथवा हामीदारों और/अथवा अन्य परामर्शदाताओं अथवा अन्यथा तय करने हेतु प्राधिकृत होगा."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण प्रतिबद्धता और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के प्रावधानों, संबद्ध स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीबद्धता व्यवस्था के प्रावधानों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम, 1970 के प्रावधानों, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स और मीटिंग्स), विनियम, 1998 के प्रावधानों, सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों, विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और विदेशी विनियम प्रबंधन (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारीकरण), 5000, और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) और अन्य सभी आवश्यक प्राधिकरणों जिन्हें संयुक्त रूप से ("सक्षम प्राधिकारी" के तौर संदर्भित किया है) के अनिवार्य अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और/अथवा स्वीकृतियों के अधीन और ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति देते समय उनके द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन, और/अथवा स्वीकृति (जिन्हें इसमें "आवश्यक अनुमोदन कहा गया है") निदेशक मंडल अपनी सम्पूर्ण विवेकाधीन शक्ति के आधार पर समय-समय पर एक अथवा अधिक शृंखलाओं में वारंट के सिवाय इक्विटी शेयरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों, जो बाद में किसी समय इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय अथवा विनियम योग्य हैं, को सेबी आईसीडीआर विनियमों अथवा उस समय लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित कीमत, नियम एवं शर्तों एवं अन्य प्रकार से तथा सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI में यथानिर्धारित अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के अनुसार, किसी नियोजन दस्तावेज और अथवा अन्य ऐसे दस्तावेजों/लेखों/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) को बोर्ड इस प्रकार निर्गम प्रस्ताव एवं आबंटन कर सकेगा कि बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी में केंद्र सरकार की धारिता किसी भी समय 51% से कम न हो."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि" सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार अर्हतापात्र संस्थागत नियोजन के मामले में:

ए) प्रतिभूतियों का आबंटन, सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के निहितार्थों में सिर्फ अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा एवं ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णता चुकता होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन, इस संकल्प के पारित होने की तारीख से 12 महीनों के अंदर पूर्ण किया जायेगा.

बी) सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 176(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक विनियमों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम कीमत पर अधिकतम 5% की छूट पर शेयर, प्रस्तावित करने हेतु अधिकृत है.

सी) प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत के निर्धारण की संगत तारीख, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार तय होगी.

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि निर्गम के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान करते समय एवं आबंटन, लिस्टिंग करते समय बोर्ड को यह अधिकार व शक्ति प्राप्त होगी कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/वे स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है या ऐसे ही अन्य उचित प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में चाहे गए या दिए गए संशोधनों, जिनसे बोर्ड सहमत हो, को स्वीकार किया जाए."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि एनआरआई, एफआईआई एवं/अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नए इक्विटी शेयर्स/प्रतिभूतियों, यदि कोई है, का निर्गम एवं आबंटन, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999, यथालागू, के अंतर्गत आरबीआई के अनुमोदन के अधीन, परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर होगा."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी करने के उद्देश्य से, निदेशक मंडल, अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, परामर्शदाताओं एवं/अथवा बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श कर एतदद्वारा निवेशकों की श्रेणी, जिन्हें शेयर्स/प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर्स/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्यन (प्रीमियम सहित, यदि कोई है), अंकित मूल्य, निर्गम/प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन/वारंट के प्रयोग/ प्रतिभूतियों के मोचन पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, मोचन अवधि, प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन अथवा मोचन अथवा निरसन पर इक्विटी शेयर्स एवं अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य, निर्गम/प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन पर प्रीमियम अथवा छूट, ब्याज दर, संपरिवर्तन की अवधि, रिकॉर्ड अथवा बही बंदी की तिथि का निर्धारण तथा अन्य सम्बंधित अथवा प्रासंगिक मामले, भारत एवं/अथवा विदेश में एक अथवा एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता, निदेशक मंडल जो भी अपने संपूर्ण विवेकाधीन उचित समझे, सहित निर्गम(मों) का स्वरूप एवं नियमों का निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत है और रहेगा."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि इस तरह के उन शेयर्स/प्रतिभूतियों, जो अभिदत्त न हों, को निदेशक मंडल अपने संपूर्ण विवेक के अंतर्गत उस प्रकार से, जैसा निदेशक मंडल उचित समझे और जैसा विधि द्वारा अनुमत हो, के अनुसार निपटान कर सकेगा."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए बोर्ड को उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिन्हें बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझा जाता हो और इक्विटी शेयर के निर्गम से संबंधित उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह के निपटान हेतु प्राधिकृत किया जाता है तथा आगे इसके पूर्ण विवेकाधिकारों में सही, उचित एवं वांछित समझे जाने वाले उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों, विषयों को करने, सभी दस्तावेजों, लेखनों को निष्पादित करने, जो आवश्यक वांछित व इष्टकर हो, को शेयरधारकों द्वारा इस प्रस्ताव से प्रदत्त अधिकारों से स्पष्टतः उनका अनुमोदन, अंतिम अधिकार व संकल्प मानते हुए उनकी आगे और किसी सहमति, अनुमोदन के बिना, करने हेतु बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है."

"आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रभावकारी बनाने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को अपनी सभी या किसी भी शक्ति को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक (कों) अथवा ऐसे किसी उपयुक्त अधिकारी(यों) को, जो वह उचित समझे, प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है."

नोट :

1. व्याख्यात्मक विवरणी
   बैठक के कार्यकलापों के संबंध में प्रमुख तथ्य स्थापित करता व्याख्यात्मक विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं.
2. प्रॉक्सी की नियुक्ति
   बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक, अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकते /सकती हैं और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है.
   प्रॉक्सी को नियुक्त करने संबंधी लिखत, चन्दरमुखी, नरीमन पॉईंट मुंबई, 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात शुक्रवार, दिनांक 21 जून, 2019 को सायं 5.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जाना चाहिए जोकि 23 जून, 2019 रविवार, अवकाश दिवस के एकदम पहले का कार्यालयीन दिवस है.
3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति
   किसी कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उस बैठक, जिसमें उसे विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रस्ताव की प्रति चन्दरमुखी, नरीमन पॉईंट, मुंबई, 400021 में स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात शुक्रवार, दिनांक 21 जून, 2019 को सायं 5.00 बजे या उसके पूर्व तक प्रस्तुत न कर दी जाए जोकि 23 जून, 2019 रविवार, अवकाश दिवस के एकदम पहले का कार्यालयीन दिवस है.
4. बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी शेयरधारक का प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा.
5. शेयरधारकों के रजिस्टर का बंद होना:
   बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण बहियां, दिनांक 25 जून (मंगलवार), 2019 से दिनांक 28 जून, 2019 (शुक्रवार) (दोनों दिन शामिल है) तक बंद रहेगी.
6. कंपनी नियम 2014 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के अनुपालन एवं सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) अधिनियम 2015 के विनियमन 44 के अनुपालन में अथवा इसमें किए गए संशोधनों के अनुसार बैंक वोटिंग के वैकल्पिक माध्यम के तौर पर रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तावित करता है ताकि सदस्यगण अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे पाएं. कंपनी द्वारा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. के साथ रिमोट ई-वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गयी हैं.
7. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति जिसमें सम्पूर्ण तुलपत्र, लाभ एवं हानि खाता, निदेशक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक रिपोर्ट, एजीएम नोटिस संपूर्ण लेख के साथ साथ ई-वोटिंग का तरीका एवं प्रक्रिया, प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और प्रवेश पास इत्यादि शामिल है, एवं इसे उन सभी शेयरधारकों, जिनके ई-मेल आईडी उपलब्ध हैं, उन्हें हरित पहल उपायों के तौर पर ई-मेल द्वारा भेजे जा रहे हैं एवं जिनके ई-मेल आईडी उपलब्ध नहीं है, उन्हें उपर्युक्त दस्तावेजों की प्रमुख विशेषताओं के साथ प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और प्रवेश पास युक्त संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट भेजी जा रही है.
   इसके अलावा उक्त सम्पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट एवं संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट हमारे बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in के 'इन्वेस्टर रिलेशन्स' लिंक पर भी अपलोड किया जा रहा है और वे कार्यालय समय के दौरान बैंक के प्रधान कार्यालय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे.
8. शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक में कोई उपहार या उपहार कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे.

निदेशक मंडल के आदेश से
हस्त
(आनंद कुमार दास)
उप महाप्रबंधक / कंपनी सचिव

स्थानः मुंबई
दिनांक: 22.05.2019

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

कॉर्पो. कार्या. प्रधान कार्यालय : चंदरमुखी, नरीमन पॉईंट, मुंबई - 400 021

सूचना

याद्वारे सूचना दिली जाते की, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या भागधारकांची 12 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार, दिनांक 28 जून, 2019 रोजी दुपारी 12.00 वाजता चंद्रमुखी, नरीमन पॉईंट, मुंबई - 400021 येथील बँकेच्या 9 व्या मजल्यावरील प्रधान कार्यालयात खालील व्यवहार पार पाडण्यासाठी भरविली जाईल:

1) 31 मार्च 2019 रोजी बँकेचे लेखापरीक्षित स्टँड अलोन आणि समेकित बॅलेन्स शीट, 31 मार्च 2019 रोजी संपलेल्या वर्षासाठी बँकेचे स्टँड अलोन आणि एकत्रित नफा आणि तोटा खाते, बँकेच्या कामकाजावर विशिष्ट चालावबीसाठी बँकेच्या कार्यकारी संचलाक मंडळाचा अहवाल आणि लेखा परिक्षकांच्या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी, मंजुर करण्यासाठी आणि स्वीकारण्यासाठी.

2) एफपीओ / राइट इश्यु / क्यूआयपी इ. द्वारे भांडवलाची उभारणी करणे.

खालील विशेष ठरावांवर विचार विनिमय करून उपयुक्त बाटल्यास, बदलांसहित किंवा बदलांविना पारीत करणे:

''ठराव असा की बँकिंग कंपनी (संपादन आणि आस्थापन हस्तांतरण) कायदा, 1970 (कायदा), राष्ट्रीयीकृत बँका (व्यवस्थापन आणि तुरळक तरतुदी) योजना, 1970 (योजना) आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (समभाग आणि सभा) नियमावली, 1998, वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार, आणि भारत सरकार (जीओआय), भारतीय रिझर्व बँक (आरबीआय), सिक्युरिटीज ॲण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) आणि / किंवा यासंदर्भात आवश्यक इतर कोणत्याही प्राधिकरणांच्या मान्यता, संमती, मंजुरी, काही असल्यास; आणि यांच्या अधीन राहून आणि त्यांनी सदर मंजुऱ्या देताना लिहून दिलेल्या सदर नियम, अटी आणि सुधारणांच्या अधीन राहून आणि सेबी (इश्यू ऑफ केपिटल ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्ट्स) नियमावली 2018 (सेबी आयसीडीआर नियमावली) आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्ट्स) नियम, 2015 (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) आणि आरबीआय, सेबी, अधिसूचना / परिपत्रके आणि बँकिंग नियम अधिनियम, 1949, सिक्युरिटीज ॲण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ॲक्ट, 1992 आणि इतर सर्व लागू कायदे आणि इतर सर्व संबंधित प्राधिकार्यांद्वारे वेळोवेळी सुचविलेले दिशानिर्देश, काही असल्यास आणि लिस्ट एएमेंट्समध्ये अधीन असलेल्या स्टॉक एक्सचेंजमध्ये जेथे बँकांचे इक्विटी शेअर्स सूचीबद्ध असतात, बँकेच्या समभागधारकांची संमती दिली जाते आणि त्याद्वारे बँकेच्या संचालक मंडळाला (त्यानंतर पुढे 'मंडळ') तयार करणे, ऑफर करणे, जारी करणे आणि बाटप करण्यासाठी (या तरतुदीसह) या मांडवलाद्वारे समाविष्ट असलेल्या अधिकार बाएरण्यासाठी कॅपिटल राइजिंग कमिटी समाविष्ट केली गेली आहे किंवा / पुन्हा तयार केली जाऊ शकते. फर्म आवंटन आणि / किंवा विषयाच्या अशा भागाच्या स्पर्धात्मक आधारावर ऑरक्षण आणि कायद्याद्वारे परवानगी असलेल्या व्यक्तींच्या अशा श्रेणींसाठी ऑफर डॉक्युमेंट / द्वारे) सेंक्टस किंवा अशा इतर कागदपत्रांमध्ये, भारतात किंवा परदेशात, अशा प्रकाराच्या इक्विटी समभागांची किंमत रु. 5,000/- कोटी (केवळ पाच हजार कोटी रुपये) (कोणत्याही प्रीमियमसह, असल्यास) अशा प्रकारे केंद्राकडे नेहमीच बँक ऑफ पेड-अप इक्विटी भांडवलाच्या 51% पेक्षा कमी नसावे, जरी एक किंवा अधिक टप्प्यांत, एक किंवा अधिक सदस्यांमध्ये बँक, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय ('अनिवासी भारतीय'), कंपन्या - खासगी किंवा सार्वजनिक, गुंतवणूक संस्था, संस्था, ट्रस्ट, संशोधन संस्था, पात्र संस्थात्मक खरेदीदार ('क्यूआयबी'), परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदार ('एफआयआय'), बँका, आर्थिक संस्था, भारतीय म्युच्युअल फंड, व्हेंचर कॅपिटल फंड, परदेशी गुंतवणूक भांडवल गुंतवणूकदार, राज्य औद्योगिक विकास महामंडळे, विना कंपन्या, भविष्य निधी, पेंशन निधी, विकास आर्थिक संस्था किंवा इतर संस्था, अधिकारी किंवा इतर कोणत्याही श्रेणीचे गुंतवणूकदार ज्यांना सध्याच्या नियम / मार्गदर्शक तत्त्वे यानुसार बँकच्या इक्विटी / सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करण्यास अधिकृत आहेत. उपरोक्त कोणतेही संयोजन बँक द्वारे योग्य मानले जाईल.'

'ठराव असा कि अशी समस्या, ऑफर किंवा बाटप सार्वजनिक समस्येद्वारे (म्हणजेच फॉलो-ऑन-पब्लिक इश्यू) आणि / किंवा अधिकार समस्या आणि / किंवा खाजगी प्लेसमेंटसह, योग्य बाटप संस्था प्लेसमेंटसह किंवा त्यापेक्षा जास्त बाटप पर्यायासह आणि अशा ऑफर, इश्यु, प्लेसमेंट आणि बाटप बँकिंग कंपन्या (संपादन आणि आस्थापन हस्तांतरण) कायदा, 1970, सेबी (भांडवल आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियम, 2018 ('सेबी आयसीडीआर रेग्युलेशन्स') च्या तरतुदीनुसार केले जाये आणि रिझर्व्ह बँक, सेबी आणि लागू असलेल्या इतर कोणत्याही प्राधिकरणाद्वारे जारी करण्यात आलेली सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे आणि अशा बैठी किंवा अशा पदतीने आणि अशा अटी व शर्तींवर बोडनि आपल्या संपूर्ण विवेकबुद्धीनुसार योग्य विचार केला पाहिजे.'

'ठराव असा कि मुख्य निबंधक आणि / किंवा अंडररायटर आणि / किंवा इतर सल्लागारांशी सल्लामसलत किंवा अन्यथा अशा मंडळांशी त्यांच्या अटी व शर्तींशी सल्लामसलत करून अशा किंमती किंवा अशा रीतीने आणि आवश्यक असल्यास, टरक्ण्याचा अधिकार बोर्डकडे असेल. त्याच्या संपूर्ण विवेकबुद्धीनुसार सेबी आयसीडीआर रेग्युलेशन, इतर नियम आणि इतर सर्व लागू कायदे, नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यानुसार निर्देदक (बँका) अस्तित्वात नसतील किंवा अशा किंमतींवर निर्णय घेऊ शकतात. आयसीडीआर रेग्युलेशन्सच्या संबंधित तरतुदींनुसार निर्धारित किंमतीपेक्षा कमी.'

'ठराव असा कि सेबीच्या (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन 2015 च्या तरतुदीनुसार, संबंधित स्टॉक एक्सचेंजच्या तरतुदींनुसार बँकिंग कंपन्या (संपादन आणि आस्थापन हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 च्या तरतुदींनुसार, या तरतुदींचे पुढे समाधान केले गेले आहे, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (शेअर्स आणि मीटिंग्स) रेग्युलेशन्स, 1998 च्या तरतुदी, सेबी आयसीडीआर रेग्युलेशन्सची तरतूद, परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, 1999च्या तरतुदी आणि विदेशी विनिमय व्यवस्थापन (भाराताबाहेरील निवासी व्यक्ती द्वारे हस्तांतरण किंवा सुरक्षा जारी करणे) नियम, 2000 आणि आवश्यक असलेल्या मान्यता, संमती, परवानग्या आणि / किंवा सिक्युरिटीज ॲण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी), स्टॉक एक्स्चेंज, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय), विदेशी गुंतवणूक प्रमोशन बोर्ड (एफआयपीबी) औद्योगिक धोरण व संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआयपीपी) आणि इतर सर्व प्राधिकरणांना आवश्यकता असू शकते (त्यानंतर या सर्वांचे एकत्रितपणे 'योग्य प्राधिकरण') आणि अशा कोणत्याही अटी, मंजुरी, परवानगी आणि / किंवा मंजुरी (यापुढे 'आवश्यक मंजूर' म्हणून) प्रदान करताना अशा कोणत्याही अटी निर्धारित केल्या जाणाऱ्या मंडळाच्या अधीन असू शकतात. वेळोवेळी, एक किंवा अधिक ट्रेंडमध्ये, ईक्विटी समभाग किंवा बॉरंट्स व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही सिक्युरीटीज, जे नंतरच्या तारखेला इक्विटी समभागांमध्ये रूपांतरित किंवा एक्सचेंज करण्यायोग्य आहेत अशा प्रकारे, केंद्र सरकार कोणत्याही प्रकारे अध्याय अंतर्गत प्रदान केल्यानुसार योग्य संस्था स्थान नियोजन (क्यूआयपी) प्रमाणे योग्यतेच्या संस्थात्मक खरेदीदारांना (क्यूआयबीज्) (सेबी आयसीडीआर नियमांच्या आठव्या अध्यायात परिभाषित केल्यानुसार) बँक ऑफ इक्विटी शेअर कॅपिटलच्या 51% पेक्षा कमी नाही. एसईबीआय आयसीडीआर रेग्युलेशनचे सहाय्य प्लेसमेंट दलऐवज आणि / किंवा अशा इतर कागदपत्रे / लेख / परिपत्रके / मेमोरेंडम आणि अशा रीतीने आणि अशा किंमती, अटी आणि शर्तींनुसार बोडनि उरवलेल्या अटींनुसार एसईबीआय आयसीडीआर रेग्युलेशन किंवा कायद्याच्या इतर तरतुदींसह त्या वेळी प्रचलित असलेल्या.'

'ठराव असा कि सेबी आयसीडीआर रेग्युलेशन्सच्या चॅप्टर सहानुसार योग्य रीक्षणिक स्थानाच्या बाबतीत असे सुधारित केले गेले आहे:

अ) सिक्युरिटीजची बाटप सेबी आयसीडीआर रेग्युलेशन्सच्या चॅप्टर आठ अनुसार अर्थात् योग्य संस्थात्मक खरेदीदारांसाठी असेल आणि अशा सिक्युरीटीज पूर्णपणे भरल्या जातील आणि अशा सिक्युरिटीजची बाटप हे रिझोल्यूशन पास होण्याच्या तारखेपासून 12 महिन्यांच्या आत पूर्ण होईल.'

ब) सेबी आयसीडीआर रेग्युलेशन्सच्या नियमन 176 (1) च्या तरतुदीनुसार बँकने नियमानुसार निर्धारित केलेल्या किंमतीनुसार पाच टक्क्यांहून अधिक सूट शेअर्स ऑफर करण्याची परवानगी दिली आहे.

क) सिक्युरिटीजचे फ्लोर प्राइस निश्चित करण्यासाठी संबंधित तारीख सेबी आयसीडीआर रेग्युलेशननुसार असेल.'

'ठराव असा कि जीओआय / भारतीय रिझर्व्ह बँक / सेबी / स्टॉक एक्स्चेंज जेथे बँकांचे शेअर्स सूचीबद्ध आहेत किंवा अशा इतर योग्य प्राधिकरणांनी आवश्यक किंवा लागू केलेल्या प्रस्तावामध्ये कोणतेही बदल स्वीकारण्याचे अधिकार आणि ताकद मंडळाकडे असेल. त्यांच्या मंजुरी, संमती, परवानग्या आणि जारी करण्याची मंजुरी देणे, बाटप करणे आणि त्यांची यादी देणे आणि मंडळाने मान्य केल्यानुसार बेळ देणे.'

'ठराव असा कि एनआरआय, एफआयआय आणि / किंवा अन्य पात्र परकीय गुंतवणूकींना नवीन इक्विटी समभाग / सिक्युरिटीजचे बाटप आणि बाटप विदेशी चलन व्यवस्थापन कायदा, 1999 अंतर्गत आरबीआयच्या मंजुरी अधीन असेल परंतु लागू असेल एकूण निर्धारित मर्यादा कार्यान्वितर्गत.'

'ठराव असा कि वरिष्ठ नवीन इक्विटी शेअर्स, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (शेअर्स आणि मिटिंग्ज), विनियम, 1998, तसेच सुधारितच्या, अधिन जारी केले जातील आणि सर्व प्रकारे बँकेच्या सध्याच्या इक्विटी शेअर्सच्या समान मानले जातील आणि घोषित केलेला त्याभोवा, जर काही असेल, संबंधित निर्देशानुसार, जो त्यांची घोषणा करताना प्रचलित आहे, त्यासाठी पात्र असतील.'

'ठराव असा कि कोणत्याही समस्येचे किंवा इक्विटी समभाग / सिक्युरिटीज बाटप करण्याच्या हेतूने मंडळाला आणि त्याद्वारे गुंतवणूकदारांच्या वर्गवारीस बाद्दल घेतलेल्या गुंतवणूकीच्या क्तासह सार्वजनिक ऑफरच्या अटी निर्धारित करण्यासाठी अधिकृत केले गेले आहे, प्रत्येक किश्तमध्ये बाटप करण्यात येणाऱ्या शेअर्स / सिक्युरिटीजची संख्या, इश्यु किंमत, समस्येवरील प्रीमियम रक्कम, जसे की त्याच्या पूर्ण विवेकबुद्धीनुसार मंडळ योग्य ठरतो आणि अशा सर्व कृती, कारणे, आणि गोष्टी करणे आणि अशा कारवाई, दस्तऐवज आणि करार अंमलात आणणे. ते, त्यांच्या संपूर्ण विवेकबुद्धीनुसार, आवश्यक किंवा योग्य वाटतात, आणि कोणत्याही प्रश्नांची पुर्तता करण्यासाठी, सूचना, दिशानिर्देश किंवा सार्वजनिक ऑफर, इश्यु, बाटप आणि इश्युच्या उत्पन्नाच्या उपयोगाविषयी उद्भवणाऱ्या समस्या किंवा अडचणी सोडवण्यासाठी किंवा दिशानिर्देश देण्यास सांगू शकतात, आणि अशा बदलांमध्ये बदल, भिन्नता, बदल, हटविणे, अटी व शर्तींनुसार जोडणे आणि त्याचा पूर्ण विवेकबुद्धी, योग्य समजणे आणि प्रो बँकेच्या सर्वोत्तम हितसंबंधित, सदस्यांची पुढील मंजूरी न घेता आणि या सर्व रिझोल्यूशनद्वारे बँक आणि मंडळाला दिलेले सर्व किंवा कोणतेही अधिकार मंडळाद्वारे बापरले जाऊ शकतात.'

'ठराव असा कि मंडळाने कोणत्याही चुक रन(सं), लीड मॅनेजर(सं), बँकर्स), अंडररायटर(सं), डिपॉझिटरी(रिस), रजिस्ट्रार(सं), ऑडिटर(सं) सह अशा प्रकारच्या व्यवस्थांमध्ये प्रवेश करण्यास आणि अंमलात आणण्याची अधिकृतता दिली आहे. आणि अशा सर्व एजन्सीज ज्यात इक्विटी / सिक्युरिटीजच्या अशा ऑफरमध्ये गुंतलेले किंवा संबंधित असू शकतात आणि अशा सर्व संस्था आणि एजन्सींना कमिशन, ब्रोकरेज, फी किंवा त्यासारख्या मागनि आणि त्यात प्रवेश करण्यासाठी आणि अंमलात आणण्यासाठी अशा एजन्सीसह अशा सर्व व्यवस्था, करार, स्मरणपत्र, कागदपत्रे इत्यादी.'

'ठराव असा कि उपरोक्त प्रभावी करण्याच्या हेतूने, मंडळ, लीड मॅनेजर, अंडररायटर, सल्लागार आणि / किंवा बँकेद्वारे नियुक्त केलेल्या इतर व्यक्तींसह सल्लामसलत करून, नुसार फॉर्म आणि अटी निर्धारित करण्यास अधिकृत आहेत ज्या समभागांची गुंतवणूकदारांचे शेअर्स / सिक्युरिटीज बाटप करायचे आहेत अशा समस्यांसह (प्रत्येक) समभागांमध्ये बाटप करण्यात येणाऱ्या समभागांची / सिक्युरीटीजची संख्या, इश्यु किंमत (प्रीमियमसह, असल्यास), फेस व्हॅल्यू, प्रीमियम रकमेवर सिक्युरिटीज / बॉरंट्सचा बाफर / सिक्युरिटीजचे विभोचन, ब्याज दर, विभोचन कालावधी, ईक्विटी समभागांची संख्या किंवा रुपांतरण इतर सिक्युरीटीज किंवा सिक्युरिटीजचे रद्दीकरण किंवा रद्दीकरण, किंमत, प्रीमियम किंवा सिक्युरीटीजचे रुपांतरण / बदल यावर सूट, ब्याजदर, बदलण्याची मुदत, रेकॉर्डची तारीख किंवा पुस्तक बंद करणे आणि संबंधित किंवा प्रासंगिक प्रकरणांमध्ये, भारताताील आणि / किंवा परदेशात एक किंवा अधिक स्टॉक एक्सचेंजेसवरील सूच्या, ज्याप्रमाणे मंडळाच्या पूर्ण विवेकबुद्धीनुसार.'

'ठराव असा कि यापुढे असे शेअर्स / सिक्युरिटीजचे सब्साक्राइब केलेले नसल्यास मंडळाद्वारे योग्यरित्या विवेकबुद्धीने निपाकरण केले जाईल ज्याची कायद्यानुसार परवानगी असेल.'

'ठराव असा कि या नियाकरणास प्रभावी करण्याच्या हेतूने मंडळाला सर्व कारवाई, गोष्टी आणि अशा सर्व गोष्टी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत जे त्याच्या पूर्ण विवेकबुद्धीनुसार आवश्यक, उचित व वांछनीय आणि कोणत्याही प्रश्नाची पुर्तता करणे आवश्यक आहे. शेअर्स / सिक्युरीटीजच्या मुद्द्यांविषयी उद्भवणारी समस्या किंवा शंका आणि अशा सर्व कृती, कारणे, आणि गोष्टी करणे, अंतिम करणे आणि आवश्यक ते सर्व कागदपत्रे आणि लेखन आवश्यक, इच्छेनुसार किंवा फायदेकारक म्हणून अंमलात आणणे. त्याची पूर्ण विवेकबुद्धी कोणत्याही समभागधारकांची पुढील संमती किंवा मंजूरी किंवा समाप्ती आणि मंजूरीची आवश्यकता न घेता आवश्यक किंवा उचित आणि वांछनीय असल्याचे मानले जाते जेणेकरुन या निणर्यांच्या अधिकाराने स्पष्ट केले की शेअरधारकांना त्यांची मंजूरी दिली जाईल.'

'ठराव असा कि मंडळाला अवस्थाकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा कार्यकारी संचालक किंवा इतर कार्यकारी अधिकारी यांना दिले जाणारे सर्व किंवा कोणत्याही शक्तीचे प्रतिनिधीत्व करण्यास अधिकृत केले गेले आहे.'

टिप:

1 **स्पष्टीकरण विधान:**
ह्या बैठकीत होणाऱ्या विविध विषयांचे स्पष्टीकरण विधान देत आहोत.

2. **प्रॉक्सीची नियुक्ती:**
सभेस उपस्थित राहण्यास आणि मतदान करण्यास पात्र भागधारक, त्याच्या ऐवजी/तिच्याऐवजी उपस्थित राहण्यासाठी/मतदान करण्यासाठी प्रॉक्सीची नेमणूक करु शकतो आणि सदर प्रॉक्सी बँकेच्या भागधारक असण्याची गरज नाही.
प्रॉक्सीची नियुक्ती केलेले दस्तऐवज, चंद्रमुखी, नरिमन पॉईंट, मुंबई-400021 येथील बँकेच्या प्रधान कार्यालयात समेसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या तारखेच्या किमान चार दिवस अगोदर म्हणजे शुक्रवार दि. 21 जून, 2019 रोजी सायंकाळी 5.00 वाजता किंवा तत्पुर्वी जमा करणे आवश्यक आहे, जो एजीएमच्या 4 दिवस अगोदर असलेल्या रविवार 23 जून, 2019 ही बँकेची सुटी असलेल्या तारखेच्या लगेच अगोदरचा कामकाजाचा दिवस आहे.

3. **अधिकृत प्रतिनिधीची नियुक्ती:**
कोणत्याही व्यक्तीला सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या भागधारकांच्या कोणत्याही बैठकीत कंपनीचा किंवा कोणत्याही कॉर्पोरेट संस्थेचा योग्य अधिकाराप्राप्त प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित राहण्यासाठी, त्या व्यक्तीला अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करणाऱ्या ठरावाची अध्यक्षांनी प्रमाणित केलेली प्रत चंद्रमुखी, नरिमन पॉईंट, मुंबई-400021 येथील बँकेच्या प्रधान कार्यालयात समेसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या तारखेच्या किमान चार दिवस अगोदर म्हणजे शुक्रवार दि. 21 जून, 2019 रोजी सायंकाळी 5.00 वाजता किंवा तत्पुर्वी, जो एजीएमच्या 4 दिवस अगोदर असलेल्या रविवार 23 जून, 2019 ह्या बँकेची सुट्टी असलेल्या तारखेच्या लगेच अगोदरचा कामकाजाचा दिवस आहे, ही बँकेची सुटी असलेल्या तारखेच्या लगेच अगोदरचा कामकाजाचा दिवस आहे. त्यादिवशी जमा करण्यात आल्याशिवाय सदर व्यक्ती कोणत्याही सभेला उपस्थित राहू शकत नाही किंवा मतदान करू शकत नाही.

4. शेअरहोल्डर बँकेचा कोणताही ऑफिसर किंवा कर्मचारी अधिकृत प्रतिनिधी किंवा प्रॉक्सी म्हणून नियुक्त करु शकत नाही.

5. **शेअर होल्डर्सची नोंदणी बंद करणे:**
25 जून 2019 (मंगळवार) ते 28 जून 2019 (शुक्रवार) (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पासून शेअरधारकांची नोंदणी आणि शेअर्स हस्तांतरण पुस्तकांची नोंदणी बंद राहील.

6. कंपनी नियम 2014 (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) चे अनुपालन आणि सेबी (लिस्टिंगमधील जबाबदाऱ्या आणि प्रगटीकरण आवश्यकता) अधिनियम 2015 च्या विनियम 44 च्या अनुपालनात अथवा त्यात केले गेलेल्या बदलानुसार बँक मतदानाचा वैकल्पीक माध्यम म्हणून रिमोट ई-वोटिंगची सुविधा सहर्ष उपलब्ध करता आहे, त्यामुळे सदस्यांना त्यांचे मत इलेट्रॉनीक रूपात देता येईल, बँकने सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) च्या सहकार्याने रिमोट ई-वोटिंग सुलभतेने करण्याची व्यवस्था केली आहे.

7. वित्तीय वर्ष 2018-19 च्या वार्षिक अहवालाची संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक प्रत आणि संपूर्ण बॅलन्स शीट, नफा आणि तोटा खाते, संचालकांचा अहवाल, लेखापरीक्षकांचा अहवाल, एजीएमच्या नोटीसचा पूर्ण मजकूर, ज्यामध्ये ई-मतदान प्रक्रियेची प्रक्रिया व पदत समाविष्ट आहे/ प्रॉक्सी फॉर्म, अटेन्डन्स स्लिप आणि ट्री पास इत्यादी सर्व ई-मेलद्वारे पाठविली जात आहेत ज्यांचे ई-मेल आयडी ग्रीन इनिशिएटिव्ह मेजर अंतर्गत उपलब्ध आहे. ज्या समभागधारकांची ई-मेल आयडी उपलब्ध नाहीत त्यांचेसाठी प्रॉक्सी फॉर्म, अटेन्डन्स स्लिप आणि एंट्री पाससह वरील कागदपत्रांच्या मुख्य वैशिष्ट्यांसह एब्रिज्ड वार्षिक अहवाल पाठविला/जात आहे.
तसेच, उपरोक्त पूर्ण वार्षिक अहवाल आणि आब्रिजेड झालेला वार्षिक अहवालाची एक प्रत 'इन्व्हेस्टर रिलेशन्स' लिंकल्या अंतर्गत www.centralbankofindia.co.in या संकेतस्थळावर देखील अपलोड केली आहे आणि बँकेच्या मुख्य कार्यालयात कार्यालयीन तासा दरम्यान तपासणीसाठी उपलब्ध असेल.

8. शेअरधारकांनी कृपया लक्षात घ्याने की मीटिंगमध्ये भेटवस्तू / गिफ्ट कूपन वितरीत केले जाणार नाहीत.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
स्वाक्षरी/-
(आनंद कुमार दास)
उप महाप्रबंधक / कंपनी सचिव

स्थळ: मुंबई
दिनांक: 22.05.2019